nwda.gov.in

डिजिटल सेंसर से भूजल की निगरानी को 10 राज्य तैयार

मनीष तिवारी • नई दिल्ली

32 हजार रिकार्डर स्थापित करने की तैयारी, जल स्तर सहित उसकी गुणवत्ता की हो सकेगी निगरानी

भूजल के स्तर तथा उसकी गुणवत्ता की लगातार निगरानी के लिए केंद्र सरकार की योजना के प्रति 10 राज्यों ने भी उत्साह दिखाया है। अपने स्तर पर डिजिटल वाटर लेवल रिकार्डर लगाने का प्रस्ताव दिया है। यदि सब कुछ सही रहा तो अगले दो-तीन साल में 32 हजार से अधिक ऐसे रिकार्डरों का नेटवर्क तैयार हो जाएगा।

जलशक्ति मंत्रालय के संयुक्त सचिव (जल संसाधन विभाग) सुबोध यादव के अनुसार, भूजल प्रबंधन नियमन के तहत डिजिटल वाटर रिकार्डर जल के डाटा को लेकर पूरी स्थिति बदल देंगे। अब भूजल की निगरानी के पुराने तौर-तरीकों से काम नहीं चलेगा। इसीलिए, केंद्र सरकार ने बीस हजार डिजिटल वाटर लेवल रिकार्डर लगाने का फैसला किया है। ये वे सेंसर हैं जो जल की उपलब्धता और उसकी गुणवत्ता की रियल टाइम निगरानी में सहायता करेंगे। अच्छी बात यह है कि उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और कर्नाटक ने अपने स्तर पर 12,000 डीडब्ल्यूएलआर लगाने का प्रस्ताव दिया है। इन्हें भी केंद्रीय सेंटर से जोड़ा जाएगा। मंत्रालय ब्लाक स्तर पर इन सेंसरों को लगाएगा ताकि डाटा सभी जगह का मिले और उसमें एकरूपता भी हो। यदि भूजल के स्तर और उसकी गुणवत्ता की रियल टाइम निगरानी का तंत्र स्थापित हो जाएगा तो पानी को लेकर नीति-निर्धारण व योजनाएं बनाने के तौर-तरीके पूरी तरह बदल सकते हैं।

सुबोध यादव के अनुसार, अभी साल में चार बार डाटा लिया जाता है। इसके सटीक होने को लेकर भी आश्वस्त नहीं हो सकते, क्योंकि ये रिपोर्ट सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के माध्यम से प्राप्त होती है। इनमें अंतर हो सकता है। यदि बाकी राज्य भी इसी तरह सेंसर को लेकर उत्साह दिखाते हैं तो नेशनल वाटर इन्फारमैटिक्स जैसे डाटा सेंटर का लक्ष्य पूरा होगा और किसी भी स्थान में पानी की स्थिति की जानकारी की जा सकेगी। जरूरत पर तो एक दिन में भूजल के घटते-बढ़ते स्तर को भी जांचा-परखा जा सकेगा।

केंद्र सरकार की पूरे देश में डिजिटल वाटर लेवल रिकार्डर लगाने की योजना के प्रति राज्यों ने दिखाया उत्साह

ऐसे होगी निगरानी

केंद्रीय भूजल बोर्ड वर्तमान में 26,000 भूजल निगरानी कुओं के नेटवर्क पर आश्रित है। इनसे टेक्नीशियन अपने कौशल के आधार पर भूजल के स्तर को मापते हैं। केंद्र सरकार इन सभी कुओं में डिजिटल वाटर लेवल रिकार्डर लगा रही है, जिन्हें कुओं में स्थापित पीजोमीटर से जोड़ा जा रहा है। पीजोमीटर ही जल स्तर मापते हैं। रिकार्डर डिजिटल तरीके से डाटा मानिटरिंग केंद्र को स्थानांतरित करेंगे।